



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2008/ज्येष्ठ 16, 1930

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2008/JYAISTHA 16, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2008

विषय : चीन जन. गण., मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड तथा श्रीलंका से सस्ते मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/12/2007-डीजीएडी.—जबकि ऑल इंडिया फाइबर बोर्ड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, फरीदाबाद ने मै. शिर्डी इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई तथा मै. न्यूकैम लि., फरीदाबाद जो घरेलू उत्पादक हैं, के साथ 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने चीन जन. गण., मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड तथा श्रीलंका (जिन्हें एतद्वारा संबद्ध देश कहा जाएगा) से सस्ते मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड (जिन्हें एतद्वारा संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के कथित पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है और ऐसे पाटन संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

और चूंकि प्राधिकारी ने यह पाया है कि सम्बद्ध देश की सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के परिणामस्वरूप, किसी कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव को

निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने, जिसकी यदि वसूली की जाती है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उपयुक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार उक्त कथित पाटन की एतद्वारा जांच प्रारम्भ करते हैं।

2. विद्याराशीन उत्पाद

विद्याराशीन उत्पाद चीन जन. गण., मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड तथा श्रीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित साढ़ मध्यम घनत्व वाला फाइबर बोर्ड अथवा सादा एमडीएफ बोर्ड है, एक चैम्फर लकड़ी का उत्पाद है जो रात, ताप तथा दाब से आपस में बिपक्व गए लकड़ी अपशिष्ट फाइबर से बना होता है। इस पार्टिशन, मोड्यूलर फर्नीचरों, कैबिनेट इत्यादि हेतु व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीट 44.11 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हो और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं चीन जन. गण., मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड तथा श्रीलंका के मूल की अथवा से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष फर्क नहीं है तथा दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

3. घरेलू उद्योग

याचिका मै. शिर्डी इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई तथा मै. न्यूकैम लि., फरीदाबाद के साथ ऑल इंडिया फाइबर बोर्ड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, फरीदाबाद जो घरेलू उत्पादक हैं द्वारा दायर की गई है। इन उत्पादकों ने वर्तमान जांच से संश्लेष सूचना उपलब्ध कराई है तथा प्रस्तावित जांच में भाग लेने हेतु सहमति दी है। इन याचिकाकर्ता कंपनियों का

उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता है। मै. फॉल्स टिम्बर प्रोडक्ट्स लि., कोलकाता समान उत्पाद का केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि (क) दो याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन, भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है; (ख) घरेलू उत्पादक जो स्पष्ट से याचिका का समर्थन कर रहे हैं वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 50% से अधिक का हिस्सा रखते हैं; तथा (ग) याचिका घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से दाखिल की गई है।

प्राधिकारी ने उपर्युक्त की जांच के पश्चात् यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग हैं और याचिका उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के संदर्भ में मानदण्डों को पूरा करती है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं विशेषताओं के संदर्भ में जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उनकी समान विशेषताएं हैं। आगे यह भी दावा किया गया है कि उपभोक्ताओं ने दोनों को एक दूसरे से स्थान पर इस्तेमाल किया है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित समान उत्पाद माना जा रहा है।

5. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन, जन. गण., मलेशिया, म्यूजीलैंड, थाईलैंड और श्रीलंका हैं।

6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि चीन, जन. गण. का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य या ऐसे तीसरे देशों में कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि संगत सूचना याचिकाकर्ताओं के पास नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। जिसे बिक्री सामान्य प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा उचित लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा।

नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार हितवद्ध पार्टियों को एतद्वारा आमंत्रित किया जाता है कि वे इस अधिसूचना

में निर्धारित विशिष्ट समय सीमा के भीतर चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी उचित समतुल्य देश का सुझाव दें।

जहाँ तक अन्य देशों का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने उपलब्ध सीमा तक संबद्ध देशों में प्रचलित कीमत के अनुसार उपयुक्तता तथा घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और कच्ची सामग्री की लागत पर विचार करते हुए परिकल्पित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

7. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने आईबीआईएस (इंटरनेशनल बिजनेस इंकॉर्पोरेशन सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदे-वार आयात आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित अवधि में भारत और आयात कीमत के रूप में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा और निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों आदि के लिए समायोजनों का दावा किया है ताकि कारखाना निर्यात कीमत निकाली जा सके। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का पर्याप्त साक्ष्य है।

8. पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है जिससे संबद्ध देशों के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना निर्यात कीमत से काफी अधिक है और यह कि चीन, जन. गण., मलेशिया, म्यूजीलैंड, थाईलैंड और श्रीलंका के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों पर सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग को काफी लम्बी अवधि से पाटन द्वारा नुकसान हो रहा है। समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन पाटन से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है। यद्यपि संबद्ध वस्तु की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग उस स्थिति में भी सतत पाटन के कारण अपनी मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ है। अतः सतत पाटन द्वारा देश में क्षमताओं का उपयोग प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है। परिणामतः उत्पादन प्रभावित हुआ है। आयातित एवं घरेलू उत्पाद के बीच कीमत में पर्याप्त अंतर से घरेलू उद्योग अपनी बिक्री मात्रा बढ़ाने से बाधित हुआ है। व्यवहारिक रूप से माँग में समूची वृद्धि की पूर्ति पाटित आयातों द्वारा की जा रही है। इस प्रकार लगातार पाटन से घरेलू उद्योग को बिक्री मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में पर्याप्त कटौती हो रही है। परिणामतः पाटन से कीमत में उतनी वृद्धि नहीं हो सकी है जो उत्पादन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्यथा हुई होती। लगातार पाटन से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रतिकूलतः प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग को समूची क्षति अवधि के दौरान वित्तीय घाटा हुआ है। इसके अलावा लाभप्रदता तथा परिणामी लाभ की स्थिति और अधिक खराब हुई है। इसका लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ा है। पाटन से घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग

को प्रथम दृष्टया संबंध देशों से संबंध वस्तु के पाटन के कारण सामूहिक और संघी रूप से नुकसान हुआ है।

10. जांच की अवधि (पीओआई)

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक की है। तथापि, क्षति संबंधी जांच के लिए वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 की अवधि और जांच अवधि शामिल होगी।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबंध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतवासों/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, भारत में क्रेताओं और प्रयोजकों जो इस जांच के संबंध में ज्ञात हैं, को निर्धारित विधि और पद्धति से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर लिख सकती है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

कमरा सं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिन के भीतर सूचना देनी होगी।

13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पार्टियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश उपलब्ध करना सुलभ न हो तो उसके कारण का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

14. सार्वजनिक फाइल का विरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी सूचना उपलब्ध कराने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना अन्यथा प्रस्तुत नहीं करती है अथवा जांच में काफी बाधा डालती है, तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दृष्ट कर सकते हैं और ऐसी सिफारिशें केन्द्र सरकार को कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2008

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of Plain Medium Density Fibre Board from China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Sri Lanka.

No. 14/12/2007-DGAD.—Whereas All India Fibre Board Manufacturers Association, Faridabad with M/s. Shirdi Industries Limited, Mumbai and M/s. Nuchem Limited—Faridabad, domestic producers have filed a Petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), alleging dumping of Plain Medium Density Fibre Board (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Sri Lanka (hereinafter referred to as the subject countries) and have requested for initiation of an anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject countries and levy of anti-dumping duty on such dumped subject goods.

And, whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

2. Product under consideration

The product under consideration is Plain Medium Density Fibre Board originating in or exported from China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Sri Lanka. Plain Medium Density Fibre Board, or Plain MDF Board, is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with resin, heat and pressure. It is widely used for partitions, modular furnitures, cabinets etc. The product is classified under Customs Tariff heading 44.11. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

The petitioners have claimed that goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Sri Lanka. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those

exported from subject countries and the two are technically and commercially substitutable.

3. Domestic Industry

The application has been filed by All India Fibre Board Manufacturers Association, Faridabad with M/s. Shirdi Industries Limited, Mumbai and M/s. Nuchem Limited, Faridabad, domestic producers. These producers have provided information relevant to the present investigations and have consented to participate in the proposed investigations. The production of these applicant companies constitutes more than 50% of total Indian production. M/s. Mangalam Timber Products Limited, Kolkata is the only other domestic producer of the like article. The Authority has determined that (a) production of the two petitioner companies constitute a major proportion in Indian production; (b) domestic producers expressly supporting the application account for more than 50 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry; and (c) the application has been made by or on behalf of the domestic industry.

The Authority after examining the above, determines that the petitioners constitute domestic industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 3 of the Rules supra.

4. Like Article

Petitioners have claimed that there is no significant difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported ones from subject countries in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Both are technically and commercially substitutable and hold close resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. For the purpose of present investigation, product under consideration produced by the petitioner is being treated as like article to one imported from the subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

5. Countries Involved

The countries involved in the present investigation are China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Sri Lanka.

6. Normal Value

The petitioners have claimed that China PR should be treated non-market economy and have determined normal value in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure-1 of the Anti Dumping Rules. The petitioners have claimed that normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country or price from such third countries to other countries for the reason that the relevant information is not accessible

to the petitioners. The petitioner, have determined normal value considering cost of production in India, duly adjusted to include selling, general, administrative overheads and reasonable profit.

In accordance with Para 7 to Annexure-1 of the Rules, interested parties are hereby invited to suggest any appropriate analogue country for determination of normal value in China within the specific time limit laid down in this notification.

With regard to other countries, petitioner have claimed normal value based on constructed cost of production considering conversion cost of the domestic industry and raw material cost and utility as per price prevailing in the subject countries to the extent available.

7. Export Price

The petitioners have claimed export price of the subject goods from the subject countries as the weighted average import price in the proposed period, based on transaction wise import data provided by the IBIS (International Business Information System). Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance and inland transportation in the country of exports, port handling and port charges etc. to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of the export price for the subject goods from the subject countries.

8. Dumping Margin

Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of subject countries. There is, prima facie, evidence that the normal value of the subject goods is significantly higher than the ex-factory export price and that the subject goods are being dumped by exporters from China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Sri Lanka.

9. Injury and Causal Link

The petitioners have furnished information on various parameters relating to material injury. The domestic industry is suffering from dumping for a fairly long period. Dumping has adversely affected the performance of the domestic industry throughout the injury period. Though, the demand of the subject goods has grown up significantly the domestic industry even after that is unable to utilize their existing capacities due to continuous dumping. Persistent dumping has therefore adversely affected utilization of capacities in the Country. Resultantly, production has suffered. Significant price difference between imported and domestic product is preventing the domestic industry from increasing its sales volumes. Practically entire increase in demand is being met by dumped imports. Persistent dumping is therefore adversely affecting sales volumes of the domestic industry. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Consequently, dumping is preventing price increases that would have otherwise occurred as a result of increase in the cost of production. Persistent dumping has adversely affected profitability of the domestic

industry. The domestic industry suffered financial losses throughout the injury period. Further, profitability and consequently profits position has deteriorated further. This has directly impacted upon return on capital employed and cash profits. Dumping has adversely affected the growth of the domestic industry. *Prima facie*, the domestic industry has suffered collectively and cumulatively material injury on account of dumping of subject goods from subject countries.

10. Period of Investigation (POI)

The Period Of Investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January, 2007 to 31st December, 2007. The injury investigation period will however, cover the period 2004-05, 2005-06, 2006-07 and the Period Of Investigation.

11. Submission of information

The exporters of the subject Countries and their Government through their embassies/representatives in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to :

The Designated Authority,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping and
Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. Time limit

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them.

13. Submission of Information on non-confidential basis

In terms of Rule 7; the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

14. Inspection of Public File

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file 'containing non-confidential version of the evidence' submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPAPLAN, Designated Authority

2167 92/08-2